

The Scheme was primarily launched to improve the lot of poor people by giving them loans for their self-employment and to deploy funds for economic rehabilitation of the rural areas and its implementation should be taken up on a continual basis. Government should also take the following steps so as to ensure that the Scheme achieved its primary aims :

1. Banks should be directed to formulate detailed guidelines and allocated at least 60 per cent of loans disbursed to people residing in rural areas.
2. There should be a continuous review and monitoring of the Scheme so that new targets may be laid down after the achievement of targets fixed earlier.

(vii) Steps for the re-surrection of scent and incense sticks industry in Kannauj, Uttar Pradesh.

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज): मान्यतर उत्तर प्रदेश का नगर कन्नौज सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि सारे संसार में इत्र और अगारबत्ती बनाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व के मार्केट में कन्नौज के इत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। भारत सरकार को भारी मात्रा में व्यवसाय करने वाले लोग विदेशी मुद्रा कमा कर देते थे। वहाँ के लोग अपने घरों पर इत्र और अगार बत्ती बनाने के लिए छोटे-छोटे कारखाने लगाए थे और यह कुटीर उद्योग के रूप में चलता था। अधिकांश लोग इत्र बनाने वाली फसलों की खेती भी करते थे। उदाहरण के तौर पर मेंहदी, बेला, गुलाब, चमेली, खस आदि की, और इस खेती से अच्छी आय कमाते थे।

पिछले कुछ वर्षों से कन्नौज का यह व्यवसाय नष्ट हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कभी इसकी विकास की ओर ध्यान नहीं

दिया। बिक्री कर, आयकर और उद्योग विभाग की अड़चनों के कारण यह व्यवसाय लगभग समाप्त हो रहा है। इत्र के फसलों की खेती करने वाले किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। इस व्यवसाय में लगे सैंकड़ों कारीगर बेरोजगार हो गये और भारत सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में ह्रास हुआ।

अतः मैं इस उल्लेख के द्वारा भारत सरकार का ध्यान इस और आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कन्नौज के इत्र और अगारबत्ती उद्योग को फिर से बढ़ाने की जरूरत है। इस व्यवसाय पर लगे आयकर और बिक्रीकर को समाप्त करना चाहिये। इत्र और अगारबत्ती की खेती करने वाले किसानों को अनुदान मिलना चाहिये और सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिये। उद्योग विभाग को इस व्यवसाय में लगे कारीगरों को तकनीकी सहायता करनी चाहिए ताकि व्यवसाय बढ़ सके, हजारों लोगों को रोजगार मिले और भारत सरकार को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो।

(viii) Need to ensure allotment of reserved seats in various University Courses to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों की बात तो खूब की जाती है, लेकिन वास्तविकता उसके विपरीत है। जब दिल्ली में इन समुदायों के छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है तो देश के अन्य भागों में क्या न्याय मिलेगा? नियमानुसार शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये 22.5 प्रतिशत सीट आरक्षित